5. अखिल भारतीय समन्वित सूअर अनुसंधान प्रायोजना /

6. अखिल भारतीय समन्वित मुर्गी अनुसंधान प्रायोजना

7. खुरपका और मुंहपका रोग पर रोग विज्ञान संबंधी अध्ययन के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना।

8. पशुओं के लिए सस्ता आहार तैयार करने के लिए कृषि उत्पादों और औद्योगिक छीजन के उपयोग से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना।

इसके अतिरिक्त बहुत-सी संस्थानगत और तदर्थ अनुसंधान प्रायोजनाएं भी हैं।

इन (कथित) प्रायोजनाओं के प्रभारी अधिकारी वैज्ञानिक होते हैं जो अधिकांशतः विश्वविद्यालयों में स्थित एककों में विश्वविद्यालय के शिक्षक और भा० कृ०अ०प० के संस्थानों में स्थित एककों में अनुसंधान कार्य करने वाले वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं?

(ख) पशुपालन के क्षेत्र में किये जाने वाले अनुसंधान में मुख्य बल देसी नस्लों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास पर दिया गया है। यह कार्य देसी नस्लों में चयन के माध्यम से अथवा श्रेष्ठ विदेशी नस्लों के साथ संकर प्रजनन के द्वारा किया जाता है जिससे कि विभिन्न कृषि-परिस्थिति की अवस्थाओं के लिए उपयुक्त अधिक उत्पादन देने वाली नस्लें विकसित की जा सकें। फिर भी, मुर्गीपालन के क्षेत्र में विदेशी शुद्ध नस्लों की मुर्गियों का शुद्ध नस्ल एवं संकर नस्ल के रूप में उनकी उत्पादन क्षमता की जांच की जा रही है तथा मुर्गियों के परस्पर चयन द्वारा उनकी उत्पादकता में सुधार लाया जा रहा है। खुरपका और मुंहपका बीमारी के रोग विज्ञान के मामले में विषाणु से उत्पन्न होने वाली बीमारी तथा उनके सापेक्ष प्रकोप का अध्ययन किया गया है और यह इस बीमारी के नियंत्रण उपायों का आधार रहा है। उप-उत्पादों के उपयोग से संबंधित प्रायोजना के मामले, में, मिश्रित आहार में मिलाये जाने वाले अनेक गैर-परम्परागत आहार संसाधन तथा उनके आहार मूल्यों में सुधार लाने के लिए फसल अवशेषों के उपचार विधियों का विकास किया गया है।

इन अनुसंधान प्रायोजना के द्वारा दूध के लिए गोपशु और भैंसों, बारीक ऊन और मटन के लिए भेडों, दूध, मांस और रेशे के लिए बकरियों और अंडा तथा ब्रायलर के लिए मुर्गियों की नस्लों में सुधार लाने के लिए उपयुक्त नीतियों का विकास किया गया है। इस अनुसंधान के चलते मवेशियों की अधिक उत्पादन देने वाली नस्लों का भी विकास किया गया है।

मुंगेर के नजदीक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना की कोई यूनिट नहीं है। फिर भी, अखिल भारतीय समन्वित बकरी अनुसंधान प्रायोजना की रांची यूनिट ने रांची के ईर्द-गिर्द के पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध कराई है।

भा० कृ० अ० प० की अनुसंधान प्रायोजनाओं का मुख्य उद्देश्य देसी नस्लों के सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इन प्रायोजनाओं से प्राप्त होने वाले उच्च कोटि के जर्मप्लाजम को विकास विभागों/एजेंसियों को प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन प्रायोजनाओं की परिचालन अनुसंधान प्रायोजना और क्षेत्र यूनिट अपने आस-पास के क्षेत्रों के पशुपालकों को प्रौद्योगिकी और प्रजनन निवेश उपलब्ध कराती हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान

बाण सागर परियोजना

534 श्री केशव प्रसाद शुक्ल : : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बन रही बाण सागर परियोजना की अनुमानित लागत क्या है तथा इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) इस परियोजना में अब तक कितना कार्य हुआ है तथा कार्य की मंद प्रगति के क्या कारण हैं

(ग) क्या सरकार विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करके इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने का विचार रखती है;

(घ) इस परियोजना से कितने ग्रामों के डूब जाने की संभावना है; और

(ङ) जिन ग्रामों तथा नगरों के डूब जाने की संभावना है वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किए गए हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बाणसागर बांध परियोजना की अनुमानित लागत (1982 के मूल्य स्तर के अनुसार) 260.51 करोड़ रुपए है। परियोजना के 1990 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) बाणसागर परियोजना के चिनाई बांध का जहां तक संबंध है, दिसम्बर, 1984 तक 82 प्रतिशत खुदाई कार्य, 33 प्रतिशत चिनाई कार्य तथा 22.5 प्रतिशत कंक्रीट कार्य पूरा हो चुका है। मिट्टी तथा पत्थर भराई (राकफिल) बांध पर नीव और विच्छेद-खाई में खुदाई का 84.5 प्रतिशत और फिल्टर का 10 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। अधिग्रहीत की जाने वाली 32,534 हैक्टेयर निजी भूमि में से बांध स्थल तक जलाशय जलमग्न क्षेत्र के लिए 3752 हैक्टेयर भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है।

दिसम्बर, 1984 तक परियोजना पर कुल 67.86 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। परियोजना पर कार्य की धीमी प्रगति का कारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के भागीदार राज्यों द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं में अपर्याप्त निधियों की व्यवस्था करना है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) 100 गांवों के पूर्ण रूप से जलमग्न होने तथा 158 गांव के आंशिक रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

(ङ) जिला पुनर्वास समितियां गठित की गई हैं। पुनर्वास के लिए योजना तैयार की गई है। प्रस्तावित पुनर्वास उपायों में, जलमग्न होने वाली सम्पत्तियों के लिए मुआवजे का भुगतान, उपलब्ध होने पर खेती के लिए कृषि भूमि का आबंटन और सड़कों तथा स्कूलों को पेयजल और सामुदायिक सभागारों जैसी सामुदायिक सुविधाओं सहित माडल शहरों तथा गांवों की स्थापना करना शामिल है।

Plan for deep sea fishing

535. SHRIMATI MONIKA DAS: Will the Minister of AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any plan for deep sea fishing for the next five years;

(b) whether Government have any proposal to set up marine fishing institutions in the country;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) by when, and the number of places where such institutions are likely to be set up.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The erstwhile Exploratory Fisheries Project which has been renamed as Fishery Survey of India is being strengthened by providing additional staff and facilities through re-organisation into six zonal bases at Veraval, Malpe/Karwar, Cochin, Madras, Visakhapatnam and Port Blair to supervise fishing operation by the survey vessels.

It is also proposed to register the Rashtriya Matsya Nigam as a Public Sector Undertaking with objectives to exploit deep sea fishery resources, and to undertake commercial fishing operations. Details of investment, programmes and location of the Corporation etc. are yet to be worked out.